कोयले की मांग और आपूर्ति में अन्तराल

1104. **श्री नागमणि:**
श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोला:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न किस्मों के कोयले की घरेलू उत्पादन क्षमता कितनी है:

(ख) गत दो वर्षों में देश में कोयले की मांग एवं आपूर्ति के बीच कितना अन्तर था;

(ग) देश में विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में सीमेंट कारखानों और इस्पात संयंत्रों द्वारा कुल कितनी मात्रा में कोयले की खपत की गई?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) वर्ष 1994-95 के दौरान हुए देश में कोयले के ग्रेड-वार उत्पादन को नीचे दिया गया है:—

(मिलियन टन में)

कोककर कोयला	44.25
अ—कोककर कोयला	
ग्रेड "ए"	4.48
"बी"	22.83
"सी"	48.46
"डी"	29.64
"ई"	40.68
"एफ"	58.64
"जी"	0.05
अग्रेडिकृत	4.80
जोड़ अकोककर	209.56
कुल जोड़	**253.81**

(ख) योजना आयोग के साथ परामर्श करके जैसाकि समग्र रूप में मूल्यांकन किए गए मांग संबंधी आकंड़े और पिछले दो वर्षों के दौरान अर्थात् 1993-94 और 1994-95 में कोयले के उठान को नीचे दिया गया है:—

(मिलियन टन में)

	1993-94	1994-95
सकल मांग	268.80	268.50
	(6.00)	(5.00)
कोयले का उठान	252.87	260.64
	(2.73)	(2.67)

कोष्टक में दिए गए आंकड़े वाशरी मिडलिंग्स को दर्शाते हैं।

(ग) राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग के विकासात्मक योजनाओं के अतिरिक्त, जिसमें चालू परियोजनाओं का क्रियान्वयन, विद्यमान खानों का पुनर्गठन और अद्यसंरल च-नात्मक सुविधाएं गठित किया जाना शामिल है। सरकार ने कोयला खनन उद्योग में ग्रहीत खनन के लिए निजी भागीदारी को अनुमति प्रदान कर दी है।

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान महत्वपूर्ण क्षेत्र द्वारा उपभोग किए गए कोयले को नीचे दर्शाया गया है:—

(मिलियन टन में)

क्षेत्र	उठान
विद्युत	*169.12
इस्पात	34.56
उर्वरक	4.28
रेलवे	0.66

*इसमें 2.67 मिलियन टन वाशरी मिडलिंग्स शामिल हैं।

Worker's Abuse in Hazardous Industries

1105. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have launched a new campaign to stop worker's abuse in the various hazardous industries in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that the concerned industries in the country are violating the basic labour standard and provisions of Indian Constitution;